निकिता की पुलिस चार्जशीट में.....

पेज एक का शेष

जाम कराने में भी उसका नाम सामने आया था। निकिता तोमर मर्डर केस में 1 नवंबर को सबसे पहले गृहमंत्री अनिल विज और उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया कि इस मामले में लव जिहाद की बात सामने आई है इसलिए इसकी लव जिहाद के नजरिए से भी जांच कराई जाएगी। एक एसआईटी गठित कर दी गई है।

700 पेज की चार्जशीट

बल्लभगढ़ पुलिस ने 6 नवम्बर को इस मामले में 700 पेजों की चार्जशीट फाइल की। इसमें 60 गवाहों के जरिए बताया गया है कि किस तरह निकिता तोमर और तौसीफ के पुराने संबंध थे। वह 2018 में अपनी मर्जी से तौसीफ के साथ अपना घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन निकिता तोमर के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने तौसीफ के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। उस समय भी निकिता तोमर के माता-पिता ने तौसीफ पर .यह आरोप नहीं लगाया था कि तौसीफ धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। बहरहाल, बाद में तौसीफ का निकिता के घर वालों से समझौता हो गया। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने निकिता का बयान कराया। जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी मर्जी से तौसीफ के साथ गई थी। इसके बाद यह मामला खत्म हो गया लेकिन निकिता और तौसीफ मिलते रहे। पुलिस को ऐसे गवाह भी मिले, जिन्होंने बताया कि निकिता तौसीफ के साथ कार में घूमती थी। परिवार ने कभी इस पर ऐतराज नहीं किया और न ही कॉलेज या पुलिस में शिकायत की।

इस चार्जशीट में यह बात साफ तौर पर दर्ज है कि तौसीफ ने निकिता की हत्या पूरी योजनाबद्ध तरीके से की। उसने पहले अजरूद्दीन नामक शख्स से कथित तौर पर हथियार खरीदा, उसके बाद अपने दोस्त रेहान के साथ बल्लभगढ़ आया। हत्या के बाद वह कार में फरार हुआ और कार रेहान चला रहा था। ये सारे तथ्य वायरल वीडियो से भी पुष्ट होते हैं।

पुलिस ने इसीलिए किसी भी जगह अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले को धर्म से नहीं जोड़ा है। अगर पुलिस इसे धर्म या कथित लव जिहाद से जोड़ती तो उसे सबूत पेश करने पड़ते। निकिता के परिवार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि निकिता पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा था। कहीं कोई लिखित दस्तावेज, वीडियो या आडियो रेकॉर्डिंग नहीं है। इतना ही नहीं 2018 में जब निकिता खुद से तौसीफ के साथ चली गई थी तो उसने लौटकर यह नहीं बताया कि उस पर इस दौरान धर्म परिवर्तन के लिए तौसीफ ने कोई दबाव डाला है। अगर निकिता ने उस समय यह बयान दिया होता तो तौसीफ पर बहुत गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो जाता और पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ता। इन्हीं वजहों से पुलिस इसमें लव जिहाद तलाश नहीं कर पाई।

कौन है अजरूद्दीन

पुलिस ने इस मामले में मेवात के पुन्हाना इलाके में पड़ने वाले गांव सिहरी सिंगड़ी से अजरुद्दीन नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसी ने तौसीफ को वह देसी कट्टा दिया था, जिससे उसने निकिता पर गोली चलाई थी।

पर, अजरूद्दीन दरअसल मजदूरी करके अपना पेट पालता है। उसका हथियार बेचने से कोई संबंध नहीं है। अजरुद्दीन को लेकर 5 नवम्बर को पुन्हाना में पंचायत हुई जिसमें मेवात के सभी गांवों के लोगों ने आरोप लगाया तौसीफ को बचाने के लिए बेकसूर अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। अगर अजरूद्दीन हथियार बेच रहा होता तो उसे मजदूरी की जरूरत क्यों पड़ती। अजरुद्दीन के घर के हालात बयान कर रहे हैं कि उसका हथियार बेचने से कोई संबंध नहीं है।

एमएलए आफताब का इनकार

जिन दिन निकिता की हत्या हुई, उस दिन कांग्रेस विधायक आफताब अहमद बरोदा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। उन्हें तब तक पता नहीं था कि तौसीफ का संबंध उनसे जोड़ दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के किसी भी पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूर्जर या हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मामले में आफताब अहमद का नाम नहीं लिया। लेकिन हिन्दूवादी संगठन ही आफताब पर तौसीफ को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे। आखिरकार आफताब ने निकिता तोमर की हत्या की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि तौसीफ का उनसे कोई संबंध नहीं है। जिन लोगों ने निकिता की हत्या की है, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनके पास या किसी भी आला अफसर के पास तौसीफ को बचाने के लिए किसी भी तरह का दबाव या फोन नहीं आया। पुलिस अफसरों का कहना है कि सजा देना अदालत का काम है। हम कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

आखिर क्या चाहता है निकिता का परिवार

निकिता तोमर का परिवार बल्लभगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट है। परिवार का कहना है कि उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। हमें पुलिस और जिला प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन हमारी कुछ और मांगे हैं जो हमने सरकार के सामने रखी हैं। निकिता के परिवार ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूर्जर हमारे घर आये थे तो हमने वो मांगें उनके सामने रखी थीं। ये तीन मांगें हैं ङ्क नए बन रहे कॉलेज का नाम निकिता तोमर के नाम पर रखा जाए, निकिता के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार की आर्थिक सहायता के लिए एक करोड़ रुपये दिये जाएं।

अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि निकिता की मौत की कीमत क्या भाई की सरकारी नौकरी, एक करोड़ रुपये और कॉलेज का नाम रखने भर से मिल जाएगी। क्या वो हिन्दूवादी संगठन राज्य की भाजपा सरकार अब दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे....जो निकिता की मौत को साम्प्रदायिक रंग देकर बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के माहौल को खराब करना चाहते थे, दंगे कराना चाहते थे। निकिता के पिता ने साफ-साफ कहा है कि बल्लभगढ़ में हिंसा करने वाले बाहर से आये थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ अराजक तत्वों को बाहर से बल्लभगढ़ लाकर दंगा कराने की कोशिश की गई थी।

मजदूर मोर्चा ने अपने पिछले अंक में बाहरी तत्वों को लाकर माहौल खराब कराने के बारे में लिखा था लेकिन पुलिस कमिश्नर ने अभी तक यह जवाब नहीं दिया कि भीड़ को भड़काने वाले कथित नेता के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की गई है। 'अपना घर' से मुस्लिमों को निकालने की धमकी देने वालों पर क्या एक्शन हुआ है।

खबर मरम्मत

जुम्मन मियां पंक्चर वाले

बिडम्बना : करें इन्तजार पर ट्रम्पवा गद्दी छोड़ने को न है तैयार

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं लेकिन वहां के उलझाऊ चुनावी नियमों के कारण स्थिति दिन पर दिन अस्पष्ट होती जा रही है। एक तरफ़ बाईडन नये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ़ ट्रम्प गद्दी से चिपके रहने की। नियमों के मुताबिक 20 जनवरी 2021 को नये राष्ट्रपति ने पद संभालना है। उससे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को व्हाईट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति भवन) में पर्याप्त सथान दे दिया जाता है ताकि वो वहां से कार्य करना शुरू कर सके और नियम कायदों से अवगत हो सकें। वहां की गुप्तचर संस्थायें सीआईए, एफ़बी आई आदि भी दोनों राष्ट्रपतियों को रिपोर्ट करना शुरू कर देती है। यह सत्ता के सुगम हस्तांतरण के लिये अच्छा इन्तजाम है। लेकिन ट्रम्प ने कह दिया है कि वह चुनाव जीत चुके हैं और इसलिये वह सत्ता नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने नये चुने राष्ट्रपति बाईडन को ब्हाईट हाउस में जगह देने से इन्कार कर दिया है।

मूल समस्या यह है कि राष्ट्रपति तो पूरे अमेरिका का चुना जाता है लेकिन उसे चुनने के लिये वहां के हर राज्य के नियम अपने-अपने हैं। कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। चुनाव में पड़े वोट किस तारीख तक स्वीकार किये जायें इसके भी स्पष्ट और अलग-अलग नियम हैं। किसी अस्पष्टता की स्थिति में कई राज्यों में गवर्नर भी चुनाव प्रतिनिधि भेजने को अधिकृत है। जनता द्वारा चुने गये ऐसे प्रतिनिधियों की कान्ग्रेस की बैठक जो नये राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अगर इसमें कोई फैसला नहीं हुआ तो सीनेट जिसमें ट्रम्प का बहुमत है वह फैसला लेगी जो ट्रम्प के पक्ष में होगा अगर ट्रम्प 20 जनवरी को ख्हाईट हाउस नहीं छोड़ते हैं तो वहां के कर्मचारी, आर्मी, सीआईए आदि सभी सरकारी संस्थाएं उनको रिपोर्ट करना बंद कर सकती है। लेकिन यह सब दिखावा है। पूंजीवादी लोकतंत्र में असली निर्णय तो पूंजीपतियों को लेना है। अगर उनको उपने मुनाफ़े के लिये ट्रम्प रास आता है तो उसे बनाये रखने का कोई न कोई बहाना वे ढूंढ ही लेंगे । इन्तजार कीजिये पूंजीवादी लोकतंत्र के गढ में लोकतंत्र की पोल खूलने वाली है।

फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों के सहारे पार्टियां

निकम्मी राजनैतिक पार्टियों में खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के सहारे चुनाव जीतने का प्रचलन बढा है। हरियाणा में बबीता फ़ौगाट, संदीप, योगेश्वर दत्त और सोनाली फोगाट इसके उदाहरण है। बबीता फोगाट तो डीएसपी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ी और हार चुकी हैं। योगेश्वर भी पिछला चुनाव डीएसपी पद से इस्तीफ़ा देकर लड़े थे और हार गये थे। न तो इन खिलाड़ियों को खेलों में कोई नई प्रतिभा पेदा करने में रूचि है और न सरकार को। इनको बस मलाईदार पद चाहिये और राजनैतिक पार्टियों को उनके सहारे वोट। ऐसे में योगेश्वर को दूसरी बार हराकर (हालांकि यह हार शायद जातिवादी समीकरणों के कारण हुई) जनता ने अच्छा संदेश दिया है कि खिलाड़ी होने का सिला राजनीति में नहीं दिया जायेगा। खिलाड़ी हो तो खेल विभाग में कोच लगिये और काम कीजिए वरना राजनीति में आपको आपके राजनीतिक काम से ही आंका जायेगा।

सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चे....

पेज एक का शेष

शिक्षक अपने वेतन का 1 फीसदी पैसा नियमित देने लगे। कुछ शिक्षकों और जनता ने 50 और 100 रुपये भी इस कोष में दिये। इस अभियान के जरिये जब सरकारी स्कूलों के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मदद मिल रही थी तो कुछ लोगों को रितु चौधरी की यह पहल हजम नहीं हुई।

उन्होंने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए हरियाणा सरकार से शिकायत कर दी। एक शख्स ने तो लोकायुक्त तक से शिकायत कर दी। हालांकि लोकायुक्त की जांच के दायरे में इस तरह की गतिविधि नहीं आती है। लेकिन जलनखोरों की दुनिया में कमी नहीं है। शिकायतों से परेशान होकर उन्होंने यह अभियान तो रोक दिया लेकिन फौरन बाद ही वह सेलफोन बैंक और कर्मा बैंक बनाने में जुट गईं। उन्होंने एक कारवां बनाया जो बढ़ता ही जा रहा है और जलनखोर घरों में दुबक कर बैठ गए हैं। देखना है कि आला सरकारी अफसर इस महिला अधिकारी को अपना मिशन कहां तक पूरा करने देते हैं। आमतौर पर भ्रष्ट अधिकारी और बेईमान नेताओं का गठजोड़ रितु चौधरी जैसे कर्मठ अफसरों को टिकने नहीं देता और उनका तबादला कर देता है।

आप कैसे मदद कर सकते हैं

अगर आप भी सरकारी स्कूलों के गरीब और जरूरतमंद बच्चे-बच्चियों की मदद करना चाहते हैं तो सेक्टर 16, फरीदाबाद में डीईईओ दफ्तर में रितु चौधरी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नया मोबाइल खरीदकर देना है। अगर आपके घर में थोड़ा पुराना मोबाइल ठीक हालत में है, तो भी आप डीईईओ या 8 सदस्यीय कमेटी को दे सकते हैं।

जिनके पास बहुत महंगे फोन हैं और उसके अलावा दो-तीन फोन रखते हैं, वो भी कम से कम एक फोन तो गरीब बच्चे की आनलाइन पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा समर्थवान लोग कर्मा बैंक के लिए स्टेशनरी, किताबें, रबड़, पेंसिल देकर सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अगर आप आठ सदस्यीय कमेटी के पास मोबाइल फोन जमा कराना चाहते हैं तो सेक्टर 8 सीही के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल जयप्रकाश, बल्लभगढ़ के घरौरा के सरकारी स्कूल में इंग्लिश लेक्चरर विनोद कुमार, बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूल में शिक्षिका श्रीमती नीना अहलावत, सेक्टर 55 के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सतेंद्र कुमार सोरौत, फरीदपुर के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल श्रीमती रंजना मेहता, एनआईटी 3 के सरकारी स्कूल में लेक्चरर राजेश, सेक्टर 21 डी के सरकारी स्कूल में लेक्चरर श्रीमती सरिता यादव और बदरपुर सैद गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक गजेंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई एनजीओ सरकारी स्कूल के बच्चों की मदद करना चाहता है तो वो भी डीईईओ रितु चौधरी से संपर्क कर सकता है।

मोदी सरकार व भाजपा शासित राज्य सरकारों की नीतियों की आलोचना करने व प्रशासन की कमियों व भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को यूएपीए जैसे काले कानून के तहत जेलों में डाल रखा है, लेकिन तब अर्णब की गिरफ़्तारी के विरोधियों को प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपातकाल और फ़ासीवादी के खतरे का अहसास नहीं हुआ।

बुटाना में गैंगरेप की शिकार दलित लड़की की मां द्वारा इंसाफ़ की गुहार लगाने वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार, डीजीपी हरियाणा और एसपी सोनीपत को नोटिस देकर जवाब-तलब करने को 'बुटाना गैंगरेप और फ़र्जी एनकाऊंटर कांड में डीजीपी हरियाणा और एसपी सोनीपत से जवाब तलब' में उजागर किया गया है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

भाजपा ने कभी पत्रकारों के दर्द को समझा भी है?

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 8-14 नवम्बर 2020 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक तथा उसकी माता कुमुद नाइक को खुदकुशी के लिये उकसाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के अर्णब को गिरफ़्तार करने पर आरएसएस व भाजपा के शीर्ष नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री अमितशाह सहित मोदी सरकार के कई मंत्रियों तथा समर्थकों ने एक सुर में इसे प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, आपातकाल जैसी स्थिति और मुंबई पुलिस के कदम को फासिस्ट करार देकर निंदा करनी शुरू कर दी। 'चोट अर्णब को लगी, घायल हुए मोदी!',

'दर्जनों बेकसूर पत्रकारों को गिरफ़्तार कराने वाले अर्णब की गिरफ़्तारी पर क्यों मचा रहे हैं शोर-सैंकड़ों बेकसूर कथित देशद्रोह के आरोपी जेलों में बंद, कभी भाजपाइयों ने उनके बारे में सोचा?' तथा 'गौरतलब: एक तरफ़ भाजपा की गोद में बैठा अर्णब, दूसरी तरफ़ संघर्षरत मज़दूर मोर्चा का मामला' में अर्णब गोस्वामी प्रकरण तथा संघ व भाजपा व मोदी सरकार की बौखलाहट का पर्दाफ़ाश किया गया है।

ध्यान रहे कि अर्णब को दुष्प्रचार अभियान के लिये गिरफ़्तार नहीं किया गया जिसे बोलने की आज़ादी पर हमला कर सकते थे। लेकिन घटनास्थल पर मिले सुसाइड नोट के अनुसार अर्णब को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। इस प्रकार यह महज एक अपराधिक केस है, न कि प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का।

बल्लबगढ़ कॉलेज की छात्रा निकिता तोमर की उसके पुराने सहपाठी तौसीफ़ द्वारा अपहरण करने में नाकामयाबी के बाद गोली से हत्या को हिन्दुत्ववादी दलों व संगठनों ने वीडियो व व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए साम्प्रदायिक रंग देकर दंगा कराने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की नाकाम कोशिश का 'क्या पुलिस को बल्लबगढ-फ़रीदाबाद में दंगा होने का इंतजार है, गुंडा तत्व पकड़ से बाहर' तथा 'अराजक तत्वों के वीडियो पर पुलिस कमिश्नर और ज़िला प्रशासन क्यों है खामोश' भंडा-फ़ोड़ किया गया है।

गौरतलब है कि ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप व वीडियो का इस्तेमाल दिल्ली दंगों के दंगाइयों द्वारा अफ़वाहें और पुलिस अभी तक किसी की तरह बल्लबगढ के असली अराजक तत्वों को पकड़ नहीं पाई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निकिता की हत्या पर लवजिहाद के खिलाफ़ कडा कानून बनाने की घोषणा के बाद हरियाणा, असम और मध्यप्रदेश ने भी ऐसा ही कानून बनाने पर विचार करने की बात कही। इसके बाद आरएसएस तथा विश्व हिन्दू परिषद ने भी भाजपा शासित राज्यों पर लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। दरअसल हिन्दू और मुसलमान बालिग लड़के-लड़कियों के आपसी मेलजोल और विवाह को रोक कर साम्प्रदायिक उन्माद व तनाव पैदा करना संघ परिवार और भाजपाई सरकारों का प्रमुख एजेंडा रहा है।

मोदी सरकार व हरियाणा की खट्टर सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' के बावजूद हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ़ अपराध बढते ही जा रहे हैं। 'हरियाणा में न तो छोरी बचाई जा रही, न पढाई जा रही' में हरियाणा में महिला विरोधी अपरोधों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

बुटाना गैंगरेप कांड में आलोचना और विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने बल्लबगढ़ में निकिता की हत्या में लवजिहाद का एंगल उछाल दिया, जबकि एसआईटी ने चार्जशीट में लवजिहाद के एंगल में को शामिल नहीं किया है। क्योंकि पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपितों का किसी भी जिहादी संगठन से जुड़ाव सामने नहीं आया है।